‘सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग मैंने नहीं रखी, यह तो पूरा राजस्थान गा रहा है’

एस.सी. आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी बैरवा ने इस संदर्भ में आगे यह भी कहा कि, उनकी इस मांग करने का बदला एस.सी. आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की फाइल रोक कर लिया गया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रॉबर्ट वाड्रा द्वारा किये गये 125 बीघा जमीन घोटाले पर एक्शन कब लेंगे? पूनिया ने इस प्रकरण में गहलोत सरकार की संलिप्तता का भी आरोप लगाया और कहा कि, गहलोत सरकार इस प्रकरण पर पर्दा डालने में जुटी हुई हैं।

जयपुर, 29 दिसम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में ए.आई.सी.सी. के प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा से राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने मुलाकात की तथा प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तौर पर पेश करने का उनसे बदला लिया गया।

बैरवा ने रंधावा से कहा कि उन्होंने सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग भर रखी थी और इसका खामियाजा उन्हें अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की फाइल से चुकाना पड़ा। बैरवा ने जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की

- **गहलोत के बजट पेश करने की बात पर कहा- अभी कौन सी तारीख तय हो गई, कौन सा बजट आ रहा है, इन बातों का कोई सिर पैर नहीं, ये ख्याली पुलाव है।**

ओर से अगला बजट पेश करने की बात पर कहा कि अभी बजट की न तो तारीख आई है और न आलाकमान ने कोई निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 25 सितंबर को विधायकों ने जो कुछ किया, उससे उनके कंठ सूखे हुए हैं। गहलोत के बजट पेश करने की बात पर उन्होंने कहा कि अभी कौन सी विधानसभा की तारीख तय हो गई है, कौन सा बजट आ रहा है। इन बातों का कोई सिर पैर नहीं है। ये ख्याली पुलाव हैं। अभी विधानसभा का कोई लैटर नहीं आया है।

बैरवा ने कहा कि जब मैंने अनुसूचित आयोग का चार्ज लिया था, तभी मुख्यमंत्री ने संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी।

पंजाब, केरल जैसे कई स्टेट में पहले से ही अनुसूचित जाति आयोग का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जब राज्यसभा चुनाव थे, तो भी हमसे वादे किए गए कि इस मांग को पूरा किया जाएगा और तब हेलीकॉप्टर हमें ले जाने के लिए खड़े रहे। वह दिन था और आज का दिन है। नियम क्या है, मुझे पता नहीं। अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन मुझे आलाकमान ने बनाया है और अनुसूचित जाति को न्याय दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरा काम ही यह है। अगर मैं इनकी रक्षा नहीं कर सका तो मेरा कोई काम नहीं।

बैरवा ने कहा कि मेरी गलती सिर्फ इतनी थी, कि मैंने मीडिया को यह कह दिया था कि सचिन पायलट जैसे योग्य व्यक्ति को मुख्यधारा में लाया जाए तो कोई बुराई नहीं है। उसके बाद से फाइल मुख्यमंत्री की टेबल पर पड़ी है सब काम कम्प्लीट है, लेकिन आज तक अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है।

खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग मैंने नहीं रखी। यह तो पूरा राजस्थान गा रहा है। अभी जब यात्रा चली थी कन्याकुमारी से तो मैं मध्यप्रदेश, केरल ओर कर्नाटक गया था। वहां भी लोग यही कह रहे थे कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय आलाकमान लेगा ओर समय कभी कम नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा होता है।

खिलाड़ी बैरवा ने यह भी कहा कि आलाकमान राजस्थान पर पूरी नजर रखे हुए हैं और 2023 में राज कैसे आए उसके लिए वर्किंग चल रही है।

‘रॉबर्ट वाड्रा द्वारा हड़पी गई 125 बीघा जमीन किसानों को कब वापस मिलेगी, राजस्थान की सरकार उस पर कब पहल करेगी, कब एक्शन लेगी?: डा. पूनिया

डा. पूनिया ने यह भी कहा कि, रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले पर राहुल गांधी और अशोक गहलोत बड़े दिल का परिचय देकर, राजस्थान के किसानों की जमीनें हड़पे जाने का कोई समाधान करेंगे क्या?

जयपुर, 29 दिसम्बर (का.सं.)। भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि, इस देश में बहुत लंबे समय, 55 साल, तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला, पर इसे जनता ने 2014 में ठीक तरीके पहचाना और यही कारण था कि कांग्रेस की भ्रष्ट नीति, अराजकता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, छद्म धर्मनिरपेक्षता को हिन्दुस्तान की जनता ने नकार दिया, पर इसमें सबसे बड़ा कारण करप्शन था।

नेहरू गांधी परिवार इसमें संलिप्त रहा और पूरी कांग्रेस पार्टी के देश में शायद सैकड़ों ऐसे मसले हैं जो भ्रष्टाचार के नाते इतिहास में दर्ज हो गए।

नेहरू के मंत्रिमंडल में मेनन जब रक्षा मंत्री थे, तब एक जीप घोटाले की गूंज उठी थी, उसके बाद कालांतर में आपने देखा होगा कि, कभी बोफोर्स के नाम पर, कभी दवा घोटाले के नाम पर, कभी कोयला के नाम पर, कभी स्पेक्ट्रम के नाम पर, घोटाले की एक लंबी फेहरिस्त कांग्रेस के हिस्से में जुड़ी रही, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। इतना तो राजस्थान की और हिंदुस्तान की जनता ने सब्र कर लिया होगा, लेकिन सब्र की सीमा तब टूटती है जब नेहरू गांधी खानदान के दामाद पर सीधे-सीधे उंगली उठती है।

2008 से 2013 के बीच 125 बीघा जमीन इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक व्यक्ति को आवंटित कर दी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, बाद में यह सारी चीजें घूमते-घूमते जब इसका कनेक्शन देखा गया तो रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की कंपनी

- **डा. पूनिया ने आगे कहा, “सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा राजस्थान के किसानों की जमीन हड़पने वाले माफिया से कम नहीं हैं, मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।”**
- **उन्होंने कहा, “कांग्रेस सरकार का राजस्थान के किसानों से कोई सरोकार नहीं है, उसकी मंशा ऐसी लगती है कि “ना खाता, ना बही, सोनिया गांधी जो कहें वही सही,” वे इस तर्ज पर राज चला रहे हैं?”**

स्काइलाइट हॉस्पिटेलिटी का सीधा सीधा उसमें जुड़ाव देखा गया। कालांतर में जब यह मुददा हाइकोर्ट में गया और इसकी सुनवाई शुरू हो गई, तब इनको फिक्र हुई और कोर्ट में इस मामले को खारिज करने के लिए। लेकिन यह मामला दुबारा सुर्खियों में आ गया जब हाइकोर्ट ने उनकी अपील को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अभी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। यानी यह एक प्रकार से स्वीकारोक्ति है कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा की और उसके परिवार की कोई संलिप्तता इस लैंड अलॉटमेंट में रही है। यह मामले आटे में नमक जितने भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि नमक में आटे के भ्रष्टाचार का है।

सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा राजस्थान के किसानों की जमीन हड़पने वाले माफिया से कम नहीं हैं और जिस तरीके के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस की सरकार ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

शुचिता, नैतिकता की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर माना था कि कांग्रेस शासन में राजस्थान में तबादलों में भी भ्रष्टाचार होता है।

बहुत सारी चीजें हैं जिसकी एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन आज मेरा फोकस सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा द्वारा हड़पी गई 125 बीघा जमीन के बारे में है। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री और राहुल गांधी ने यात्रा निकाली उनसे हमने कुछ सवाल किए थे। मैं उनसे फिर पूछता हूँ कि इस तरीके से किसानों की जमीन हड़पने पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे।

कांग्रेस सरकार का राजस्थान के किसानों से कोई सरोकार नहीं है, उनकी मंशा ऐसी लगती है कि ना खाता, ना बही, सोनिया गांधी जो कहें वही सही, इस तर्ज पर वो राज चला रहे हैं।

डॉ. पूनिया ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा में कुछे चीजें बड़ी रोचक थीं, जैसे भगवान राम, जिन पर भगवान श्रीराम के कांग्रेस की धारणा समय-समय पर बदलती रहती, इनको भगवान राम जन्मभूमि पर ऐतराज था, रामसेतु पर ऐतराज था, ये जय सियाराम, जय श्रीराम के भेद को नहीं जानते। चाकूकारिता की पराकाष्ठा यह है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। एक सज्जन हैं यहां कांग्रेस में उन्होंने राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से की। हालांकि खुद राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी से मेरी तुलना नहीं हो सकती, तो फिर राम से कैसे होगी।

कुल मिलाकर कांग्रेस का जो चरित्र है चाटुकारिता का, भ्रष्टाचार का और भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानने का है।

रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जो जमीन घोटाले पर मेरा कहना है कि अशोक गहलोत या खुद राहुल गांधी, क्योंकि स्वयं राहुल गांधी के परिवार पर आरोप है, क्या उदारता से, निरपेक्षता से, ईमानदारी से बड़े दिल का परिचय देंगे और राजस्थान के किसानों की जमीनों को हड़पने जो काम किया है, उसका कोई समाधन करेंगे क्या?

प्रदेश में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

झोटवाड़ा में 1 नया मरीज मिला है। वहीं 2 संक्रमितों का पता गलत मिला है। प्रदेश में आज, गुरुवार को 9653 जांच की गई हैं।

दूसरी ओर, पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश में केवल 5 मरीज ही ठीक हुए, जिससे एक्टिव केस बढ़कर 91 हो गए हैं। इनमें 76 लोगों का इलाज जयपुर में चल रहा है।

प्रदेश में गुरूवार को करोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। ज्ञातव्य है कि, राज्य में अब तक इस बीमारी से 9653 लोगों की मौत हो चुकी है।

‘मुख्यमंत्री समकक्ष...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेताओं ने एक साथ कहा कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े नेताओं को सरकार के इनाम में जबरदस्त तवज्जो मिली है। हंगामे के बाद प्रभारी रंधावा ने इन सभी को यह आश्वासन दिया कि आगे इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा और कम से कम संगठन की नियुक्तियों में इन नेताओं को तवज्जो दी जाएगी।

रंधावा के साथ फीडबैक बैठक में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी यह स्वीकार किया कि सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के चलते उनके निर्वाचन क्षेत्रों में रह चुके कांग्रेस प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि इन विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रत्याशी इग्नोर हुए हैं, लेकिन अब रंधावा के इस तरह के फीडबैक से कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी मनीष यादव और सुभाष मील ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हम जैसे युवाओं को मौका दिया और कांग्रेस के ही बागियों के चलते हम चुनाव हारे। भाजपा के वोट हमारी विधानसभा में ना के बराबर थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बगावत करने वाले निर्दलीय एमएलए को सरकार में लाकर ताकत दी गई, जिससे न केवल हम कांग्रेस के उम्मीदवार विधानसभा में कमजोर हुए, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इन निर्दलीय विधायकों ने प्रताड़ित किया। यहां तक कि इन विधायकों के चलते कांग्रेस के साथ रहे नेताओं को पंचायत या नगरपालिका में टिकट भी नहीं दिए गए। इन उम्मीदवार रहे नेताओं ने आरोप लगाया कि निर्दलियों ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में पैसे लेकर सरकार का दुरुपयोग किया, जिससे आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हमने प्रभारी रंधावा से इस बात की शिकायत की है कि इन लोगों ने हमारे क्षेत्र में कांग्रेस को मारने का काम किया है, जिस पर उन्होंने सकारात्मक रुख भी दिखाया है और आगे संगठन में नियुक्तियों के लिए हमें आश्वस्त किया है।

फीडबैक के दौरान ही एक नेता ने सुझाव दिया कि विधानसभा उम्मीदवार छह माह पूर्व ही तय किया जाए या फिर जिसे पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है उसे इस बारे में तैयार रहने का इशारा किया जाए।

‘आरोपियों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पेपर लीक मामले पर मलिंगा ने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है कि पेपर लीक हुए हैं और इसमें कहीं न कहीं कमी है, इसे लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बेचारा गरीब आदमी जो साल के दो-दो लाख रु. खर्च कर रहा है उस पर अन्याय नहीं होना चाहिए। मलिंगा ने कहा कि छोटी-मोटी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। इस पर बड़ा एक्शन लेना होगा। पेपर लीक में कोई भी शामिल हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने आरपीएससी को लेकर कहा कि सरकारी एजेंसी क्या इसलिए बनाई जाती है कि बार-बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो उसे माफ नहीं करना चाहिए।

मलिंगा बोले कि जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं या नंबर दो के काम कर रहे हैं, उनके घर को ध्वस्त करना चाहिए। चाहे इनकी कितनी भी प्रॉपर्टी है, उस पर योगी की तरह बुलडोजर चलाना चाहिए। ये बेईमानी का धंधा है, इसे खत्म करना चाहिए।

क्षेत्रीय राजनीतिक दल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांधला, उंचा गांव और कैराना से होकर गुजरेगी।

राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा का उद्देश्य देश को प्रेम और घ्रणा से युक्त कर एकजुट करना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तीनों प्रमुख नेताओं के इसमें शामिल होने से इन्कार करने का प्रमुख कारण यह है कि यह यात्रा एक ऐसे राजय की राजनीतिक भूमि पर हो रही है जहां से लोकसभा के लिए 80 सांसद निर्वाचित कर भेजे जाते हैं।

सूत्रों ने बताया कि अखिलेश और जयन्त, दोनों ही कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश से नाराज हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हाल ही के हफ्तों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को बहुत कम महत्व दिया है।

यादव और चौधरी, दोनों का यह मानना है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार शेष नहीं रह गया है क्योंकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस के सिर्फ दो ही सांसद जीते थे। एक तो अमेठी से राहुल गांधी और दूसरा रायबरेली से सोनिया गांधी, जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी चुनाव हार गए थे। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ 2 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए थे।

सपा और आर.एल.डी. को लगता है कि यदि वे दोनों यात्रा में शामिल हो गए तो उनके समर्थकों की कांग्रेस के प्रति विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। दोनों नेता कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के रिक्त राजनैतिक स्थान को भरने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस भी उन्हें मध्य प्रदेश, राजस्थान कर्नाटक या अन्य ऐसे राज्यों में समायोजित करने के मूड़ में हीं हैं जहां उसकी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ है।

लखनऊ के प्रो. रमेश दीक्षित ने राष्ट्रदूत को बताया कि बताया कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस का व्यवहार स्वयं को श्रेष्ठ मानकर चलने वाला रहा है। प्रो. दीक्षित, जो स्वयं एक राजनेता हैं, ने कहा कि भाजपा के विरूद्ध किए जाने वाले किसी भी संयुक्त संघर्ष में कांग्रेस अपने लिए सीटों के बड़े शेयर की मांग करती है और उन सीटों पर उनके अधिकांश नेता हा जाते हैं।

उसके नेताओं में कुछ हजार से अधिक वोट प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है और भारत जोड़ो यात्रा से मिल रहे रिस्पांस से उसे भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। अपने जनाधार को वोटों में तब्दील करने के लिए कांग्रेस को और अधिक मेहनत करनी होगी।

एक परिपक्व राजनीतिक पर्यवेक्षक राम प्रसाद विभोर ने कहा कि क्षेत्रीय नेताओं में अहम बहुत है ओर इसीलिए उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि भाजपा से मुकाबला कर उसे हराया जाना चाहिए कांग्रेस के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को मांगों को कभी-कभी स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। भले से इसे पूर्णतया उचित नहीं माना जा सकता।

राज्यपाल ने विधानसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को इस सम्बंध में प्रभावी कार्य योजना बना कर कार्य करने को कहा। उन्होंने कोचिंग संस्थाओं के प्रभावी नियन्त्रण, वहां शुल्क का निर्धारण, तनाव व दबाव रहित शिक्षण व्यवस्था, साप्ताहिक अवकाश, उचित स्वास्थ्य देखभाल, योग एवं खेल के माध्यम से तनाव प्रबन्धन जैसे मुद्दों को सम्मिलित करते हुए इस सम्बंध में शीघ्र कुछ किए जाने के भी सुझाव दिए।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष विभिन्न समाचार पत्रों में पेपर लीक के संबंध में प्रकाशित खबरों पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोक सेवा के लिए कार्मिकों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाना राज्य सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। उन्होंने राज्य सरकार स्तर पर इस सम्बंध में तत्काल उचित कार्ययोजना का निर्माण करते हुए उसका कठोरता से अनुपालन करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक होना परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ छल है। इससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने पेपर लीक करने में संलिप्त कोचिंग संस्थानों, संगठित अपराधियों और भर्ती संस्थानों के पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता जताई।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल मिश्र ने मुख्यमंत्री गहलोत को पेपर लीक प्रकरण और कोटा में कोचिंग संस्थाओं में छात्र-छात्राओं की बढ़ती आत्महत्याओं में त्वरित संज्ञान लेकर कार्यवाही करने के लिए पृथक से पत्र भी लिखे हैं।

यू.पी. के क्षेत्रीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है, के राज्य-स्तरीय गठबन्धनों के लिये प्रयासरत हैं।

राहुल गांधी की यात्रा को कई विपक्षी नेताओं, जिनमें डी.एम.के. के एम.के. स्टालिन, शिवसेना यू.बी.टी. के आदित्य ठाकरे तथा एम.एन.एम. के कमल हासन भी शामिल हैं, का समर्थन मिला है, जबकि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबामुफ्ती तथा फारूक अब्दुल्ला-के यात्रा के अन्तिम चरण में शामिल होने की सम्भावना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच एकता की उम्मीदे ध्वस्त हो गई हैं।

अखिलेश यादव के अतीत के गठबन्धन अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। 2017, समझौते के अनुसार, कांग्रेस को 100 सीटें आवंटित की गई थीं लेकिन कांग्रेस केवल 7 सीटें ही जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में, बसपा, सपा की 5 सीटों की तुलना में 10 सीटें जीतकर अपेक्षाकृत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी।

इस समय, जब राहुल गांधी अपनी यात्रा के कारण, राजनैतिक आकर्षण हासिल कर रहे हैं, अखिलेश स्वयं को कांग्रेस से दूर रखना चाहते हैं। सपा के हल्कों में यह माना जा रहा है कि अगर अखिलेश, राहुल गांधी के साथ गठबन्धन करते हैं तो कांग्रेस, सपा की कीमत पर लाभ में रहेगी। इसके साथ ही, सपा के हल्कों में यह भी आशंका है कि राहुल की यात्रा छोटी-मोटी पार्टियों तथा जातिगत ग्रुपों को अपनी और खींचेगी, जिन्होंने इस साल हुये विधान सभा चुनावों में सपा को समर्थन दिया था।

तमिलनाडू सरकार अपना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। सरकार एक “स्टेट फैमिली डेटाबेस (एस.एफ.डी.बी.) है, जिसे राज्य के लिये “ सिंगल सोर्स ऑफ रेज़िडेन्ट डाटा” बताया जा हा है। ऐसा माना जा रहा है कि एस.एफ.डी.बी., जो प्रत्येक नागकि को यूनिक मक्कल आई.डी. उपलब्ध करायेगा, नागरिकों के डेटा के व्यापक भण्डार का काम करेगा।

तमिलनाडु सरकार के सूत्रों ने इस बात से इनकार किया कि प्रस्तावित आईडेन्टिफिकेशन नम्बर हर तरह से आधार जैसा ही है। आधार के विपरीत, तमिलनाडुवारियों को कोई फिज़िकल कार्ड नहीं दिया जायेगा। यह एक ऐसा बैकएन्ड नम्बर होगा, जो, भिन्न स्पैलिंग या अन्य कारणों से, किसी व्यक्ति की डुप्लीकेट पहचान से बचने में सरकार की मदद करेगा। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि मक्कल आई.डी. का उद्देश्य भिन्न-भिन्न प्रकार के डेटाबेस, जो विभिन्न सरकारी विभागों में अस्तित्व में हैं, को एकीकृत करना होगा।

लेकिन भाजपा इसके पीछे डी.एम.के. नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार की कोई ऐसी कुत्सित चाल देख रही है जिसका उद्देश्य केन्द्र सरकार के आधार कार्ड की जड़ खोदना है। भाजपा का कहना है कि आधार कार्ड की जड़ खोदना है। भाजपा का कहना है कि आधार कार्ड के जरिये भ्रष्टाचार के मामले तथा कल्याणकारी योजनाओं की अनेकानेत “लीकेज” जानकारी में आई हैं। तमिलनाडु के भाजपा उपाध्यक्ष नारायणन त्रिपाठी ने कहा, “द्रमुक सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होना चाहती है तथा यही कारण हे कि वह आधार को हटाकर, अपना निजी नम्बर लाना चाहती है, जिसमें कोई भी धांधली कर सके।

‘अब कहीं से भी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कर सकेंगे मतदान’

चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग की सुविधा देने की योजना बना रहा है तथा इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जायेगी

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर। अब देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना संभव हो सकेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से गृह नगर से देश में अन्य जगह बसे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू कर दिया है। इस पहल से प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए वापस अपने गृह राज्य / नगर जाने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को कहा कि वह घरेलू प्रवासियों के लिए

- **चुनाव आयोग की इस पहल से प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए वापस अपने गृह राज्य / नगर जाने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी।**
- **चुनाव आयोग इसके लिए एक प्रोटोटाइप आर.वी.एम. (रिमोट वोटिंग मशीन) तैयार करवा रहा है।**

रिमोट वोटिंग की सुविधा तैयार है, जिससे प्रवासी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने गृह राज्यों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल, आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आर.वी. एम.) विकसित की है और इसके प्रदर्शन के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया है।

प्रोटोटाइप आर.वी.एम. एक रिमोट पोलिंग बूथ से कई निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकता है। इसकी खूबी यह है कि यह एक रिमोट पोलिंग बूथ से ही 72 तक निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान करा सकती है। बता दें कि आम चुनाव 2019 में मतदाता मतदान 67.4 प्रतिशत था। जिस कारण चुनाव आयोग 30 करोड़ से अधिक मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने के मुद्दे के बारे में चिंतित है। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग मतदान होते हैं। आयोग ने बहु-निर्वाचन क्षेत्र प्रोटोटाइप रिमोट ई.वी.एम. सिस्टम का प्रदर्शन करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 राज्यीय दलों को 16 जनवरी 2023 को आमंत्रित किया है। इस अवसर पर आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। आयोग ने इस सिस्टम में किसी भी तरह के बदलाव या आपत्ति दर्ज कराने को लेकर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से 31 जनवरी 2023 तक लिखित जवाब देने का भी अनुरोध किया है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्स:01562-256908